राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (XII प्लान)

- उपरोक्त योजना में राजस्थान राज्य में 33 जिलों की 34 योजनाऐ बनाना प्रस्तावित है ।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की मोनेटरिंग कमेटी के समक्ष 28 योजनाऐ स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2013 को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम की उपस्थिति में ऊर्जा मंत्रालय में प्रस्तुत की गई।
- मोनेटरिंग कमेटी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, ने उपरोक्त 27 जिलो की 28 योजनाओ की स्वीकृति प्रदान की तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. द्वारा उपरोक्त 27 जिलो की 28 योजनाओ की स्वीकृती दिनांक 27.09.2013 को जारी की गई। इन परियोजनाओ की अनुमानित लागत 1453.90 करोड रूपये है।
- राजस्थान राज्य की 28 योजनाओ में 9843 अविद्युतीकृत (100 व उससे अधिक आबादी वाली) ढाणियो का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। जिसमें 4.43 लाख बीपीएल परिवारो तथा 8.92 लाख सामान्य परिवारो को घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।
- 5 जिलो की जयपुर, बांसवाडा,हनुमानगढ,धोलपुर, उदयपुर की योजनाऐं बना दी गई हैं। तथा वेब पोटल पर अपलोड किया जा चुका है। इन स्कीम को State level Standing Committee. द्वारा स्वीकृती हेतु भारत सरकार को भिजवाई जा चुकी है। 5 योजनाओ में 320 अविद्युतीकृत (100 व उससे अधिक आबादी वाली) ढाणियो का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। जिसमें 1.25 लाख बीपीएल परिवारो तथा 1.96 लाख सामान्य परिवारो को घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इन परियोजनाओ की अनुमानित लागत 402.43 करोड रूपये है।
- शेष 1 जिले की (बाडमेर) योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सह कम्पनी आरईसी पीडीसीएल द्वारा बना दी गई हैं। वेब पोटल पर अपलोड किया जा चुका है। जिसमें 0.45 लाख बीपीएल परिवारों तक 1.87 लाख सामान्य परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 413.81 करोड़ रूपये है। इस योजना में 100 व उससे अधिक आबादी वाले 1544 अविद्युतीकृत ढ़ाणियों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है।
- उपरोक्त योजनाओं में योजना की शर्त अनुसार 100 व उससे अधिक आबादी वाली ढाणियों/ग्रामों को विधुतिकरण हेतु सम्मिलित किया गया हैं।
- राजस्थान राज्य में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों/ग्रामों के विधुतिकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृती हेतु भिजवायें जा सकते हैं।
- उपरोक्त स्वीकृत 28 योजनाओ में से 8 योजनाओं (झून्झूनू, डूगरपुर, जालोर, पाली, चूरू, पी.एस.–लाडनू, सिरोही एवं श्रीगंगानगर) के कार्यदेश जारी कर दिये गये है। शेष 20 स्वीकृत योजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम /ऊर्जा मंत्रालय को विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु पत्र लिखा जा चुका है।

➢ **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** :–

- भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गयी है।
- स्वीकृति हेतू लम्बित (जयपुर, बासवाडा, हनुमानगढ, धोलपुर, बाडमेंर एवं उदयपुर) योजनाओं की स्वीकृती सम्भवतया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत की जावेगी।